

अमेरिकी गुंडागर्दी क्या परमाणु युद्ध का आहान कर रही?

## यूक्रेन को अमेरिका नाटो हथियार दे भड़का रहे युद्ध

**अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल गाजा युद्ध बंद हो पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में युद्ध रोकने की नौटंकी**

वर्तमान में अमेरिका प्रायोजित यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिकी हथियारों की बिक्री के साथ पुराने हथियारों की सफाई नई पीढ़ी के हथियारों का निर्माण परीक्षण और बिक्री से लाभ अमेरिका को हो रहा है इसलिए वह यूक्रेन को बर्बाद करवाने के साथ रूस को कमज़ोर करने के बड़यंत्र पर लगातार काम करते हुए यूक्रेन को हथियार देकर न केवल अमेरिका बल्कि पड़ोस के जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन व अन्य नाटो देश रूस की तबाही की कहानी लिखने पर आमादा है पर इसके विपरीत रूस ने खुले में अमेरिका और उसके नाटो की बड़यंत्र करने के खिलाफ खुले



में परमाणु हमले की धमकी दे दी है जिसमें स्वाभाविक है रूस चीन और उत्तरी कोरिया साथ में होंगे। बेशक अमेरिकी और उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ब्लू डकैती बीमारी फैलाना दूसरे देशों के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों पर कब्जा करने के बड़यंत्र करने की गुंडागर्दी के विरुद्ध अब विश्व में तृतीय महायुद्ध होना ही चाहिए

और अमेरिका-चीन जैसे देश का धरती से नामेनिशान मिट जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान की पूरी दुनिया में चल रही गुंडागर्दी तबाही के पीछे चीन और अमेरिका ही है। बेशक सामने से भले ही वे एक दूसरे को गलियां बकते हो पर कुछ मायने में वह बड़यंत्रकारी राष्ट्र दूसरे देशों पर अपना कब्जा जमाने के लिए एक जैसी नीति का

अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए अब भीषण परमाणु विश्व की अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचता और उसके बारे में रूस ने खुले में धमकी देकर कह दिया है कि इसे मजाक ना समझें और मजाक होनी भी नहीं चाहिए वास्तविक परमाणु युद्ध होना चाहिए। जिसका असर देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे देश व देश की जनता को बर्बाद

करने के बड़यंत्रों पर भी गहरा लंबा और तीखा होना ही चाहिए ताकि बड़यंत्रकारी सत्ताधीशों को समझ आ सके की जनता के शोषण का खेल लंबे समय तक नहीं खेला जा सकता और उसके मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें बड़यंत्रकारियों को सदा के लिए धरती से साफ कर सकती हैं। जहां तक इजरायल गाजा युद्ध का सबाल है तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि इजरायल युद्ध रोके। परंतु मुस्लिम देशों और आबादी द्वारा अमेरिकी सरकार परदबाव बनाने के साथ-साथ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल का उन मुस्लिम राष्ट्रों में बहिष्कार झेलना पड़ रहा है इसलिए अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कुछ दबाव में आकर अमेरिकी सरकार इजराइल को युद्ध रोकने का दबाव बनाती है जबकि उसकी इच्छा रोकने की नहीं फिर जैसा कि पूर्व में लिखा गया की धरती पर कहीं भी युद्ध हो वह विमान मिसाइल माल

गोला बारूद व आई नीड तो सामग्री अमेरिका की ही बिकेगी। और यही कारण है कि यूक्रेन को रूस से युद्ध करते हुए 2 साल गुजर गए परंतु वह यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रूस को परमाणु हमले के लिए उकसाने पर तुला हुआ है। जिसका भयंकर परिणाम और तबाही अमेरिका को भी देखने को मिलेगी। पुतिन ने फिर चेतावनी दी कि अगर उसकी संप्रभुता को खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।

राष्ट्रपति ल्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि अगर रूस की संप्रभुता या स्वतंत्रता को खतरा होता है तो वह परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार है, उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले पश्चिम को एक और दो टूक चेतावनी जारी की, जिसमें उनका एक और छह साल का कार्यकाल सुरक्षित होना लगभग तय है।  
(शेष पेज 7 पर)

पूरे देश के जिलों के कलेक्टरों ने इवीएम में फर्जी मतदान बढ़ाया

## इवीएम के बड़यंत्रों से लोकतंत्र की हत्या

**विपक्ष नपुंसकता से विपक्ष में ही पुनः सत्ता छल कपट से भाजपा के पास, संविधान व अनेकों कानून बदलने, निजीकरण का बड़यंत्र अब पूरा होगा**

भारत में तीसरी बार सत्ता इवीएम के छल कपट से पूरे देश की जनता के विरोध के बाद में भी हथियारों की तैयारी मतदान का प्रतिशत बढ़ा पूरी कर ली गई है। सारी संस्थाएं न्यायालयीन व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व प्रचार माध्यमों को डरा धमका और बड़यंत्रों से सबको कब्जे में कर अब सबको कठपुतली की तरह निशा कर अपनी सत्ता को स्थायित्व दिया जा रहा है। यथार्थ में देश में अब लोकतंत्र नहीं लूट और



बड़तंत्र चल रहा है।

पिछले 10 सालों में भी बहुराष्ट्रीय कंपनी और पूर्जीपतियों के इशारे पर नाचकर देश के उद्योग धंधों, रोजगार, सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य सदृकं विद्युत पानी सबका निजीकरण किया जा रहा है। स्वाभाविक है आम गरीब व मध्यमवर्गीय आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही नसीब

**मोदी सरकार ने पेगासस का कर्ज उतारने**

**27 टन विस्फोटक भेजा इजरायल**

**भारत के 27 टन विस्फोटक ले जा रहे जहाज को स्पेन ने रोका**

**समाचार पत्रों में दिए कारगिल युद्ध के समय इजरायल के गोला बारूद का कर्ज उतारा, पूरी तरह बकवास**

भारत सरकार ने इसराइल को गोला बारूद की कमी पूरा करने के लिए 27 टन गोला बारूद भरा जहाज लंबी समुद्री मार्ग से इसराइल को भेजा था जो स्पेन के बंदरगाह के सामने से गुजर रहा था उसे स्पेन नहीं युद्ध भड़काने वाला मानते हुए अपने बंदरगाह पर ही रोक दिया इसके बदले में भारत सरकार ने यह दलील दी कि इसराइल ने भारत-पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में गोला बारूद दिया था इसलिए उसका एहसान उतारने उसकी कंपनी द्वारा निर्मित गोला बारूद को इसराइल भेजा जा रहा



थाजों की पूरी तरह झूठ है सच तो यह है कि भारत सरकार ने जो अपने ही नेताओं के साथ विपक्षी नेताओं पत्रकारों अधिकारियों के मोबाइल फोन की जासूसी करने के लिए पेगासस का जो सॉफ्टवेयर लिया था। जिससे भारत में तथ्य सामने आने के बाद जासूसी के आरोप में मोदी सरकार की जो भद्र पिटी थी और उसकी जांच करवाने की बात की थी उसमें इसराइल ने कोई सहयोग इसलिए नहीं किया ताकि मोदी सरकार का सच जनता के सामने ना आए और इस सच को दबाये बनाए रखने के लिए मोदी ने 27 टन गोला बारूद इसराइल को भेजा था। जबकि भारत ईरान से पेट्रोल क्रूड लेता है व्यवसाय करता है और उसके बंदरगाह को रखरखाव संचालित करने के लिए लिया है (शेष पेज 2 पर)

## संपादकीय

जिस बात की आशंका थी वही हुआ। एग्रिट पोल के बहाने गोदी मीडिया ने मोदी की सरकार बनवा दी। वह भी सामान्य नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से। वोटों का आंकड़ा ऐसा है कि जैसे देश में मोदी के पक्ष में आंधी चल रही थी। जबकि जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। चट्टी-चौराहों और पान-चाय की दुकानों तक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बोलती बंद थी। सार्वजनिक बहस में कोई शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोग बीजेपी के खिलाफ या विपक्ष के पक्ष में या फिर अपने रोजी-रोटी और रोजगार के सवालों को लेकर इतने बोकल और हमलावर थे कि सत्ता को डिफेंड करने की कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था।

और बहस का यह पूरा मोर्चा जनता ने संभाल रखा था। जमीन पर सत्ता के खिलाफ यह अपने तरह का एक लौह प्रतिरोध था जो **24X7** काम कर रहा था। वह बिहार हो या कि हिमाचल, असम हो या कि कर्नाटक हर जगह यह इसी तरह से दिख रहा था। ऐसे में गोदी मीडिया द्वारा दिए गए तो तिहाई बहुमत की असलियत समझी जा सकती है। जमीनी हकीकत और एग्रिट पोल के आंकड़े के बीच कितना गैप है यह जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग करने वाला हर पत्रकार समझ सकता है। लेकिन चूंकि सरकार बनानी है और वह किसी भी कीमत पर बनानी है तो उसके लिए पूरा माहौल और नरेटिव तैयार करना था। और उस लिहाज से यह प्राथमिक शर्त बन जाती है।

मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मानते हैं कि मोदी-शाह की जोड़ी

सत्ता को सहज और सामान्य तरीके से अगली सरकार को सौंपने वाली नहीं है। उसके पीछे कारण है। यह कोई सामान्य लोग नहीं हैं और अपने 20-25 सालों के शासन में इन्होंने जो गुनाह किये हैं वह अक्षम्य हैं। और उसके साथ ही सत्ता में रहते जो बदले की कार्रवाइयां की हैं वो सारी चीजें इनका पीछा कर रही हैं। इसलिए दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह रिटायर होने के बाद मोदी सामान्य जीवन जी सके यह बहुत मुश्किल है। यह बात मोदी को भी पता है और राजनीति में रुचि रखने वाले दूसरे जानकारों को भी। इसलिए यह जितना जनता और लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए जीवन मरण की लड़ाई है उससे कम मोदी और शाह के लिए भी नहीं है।

यह कोई सामान्य इमरजेंसी जैसा मामला भी नहीं है। जिसमें इंदिरा गांधी ने संविधान के दायरे में रह कर सब कुछ किया था। और सामान्य और निष्पक्ष चुनाव में जब उनके खिलाफ नतीजे आए तो उन्होंने हार स्वीकार कर सत्ता से बाहर हो गयीं। और फिर उसी तरह से तीन साल बाद हुए चुनाव में फिर से सत्ता में आ गयीं। लेकिन मोदी-शाह ऐसे नहीं हैं। वो बगैर इमरजेंसी के ही इमरजेंसी से बड़ी तानाशाही लागू किए हुए हैं। ये न तो संविधान में विश्वास करते हैं और न ही किसी नियम और कानून में। इनके लिए न तो कोई नैतिक मानदंड है और न ही सिद्धांत का कोई मसला।

और जरूरत पड़ी तो सत्ता के लिए अपराध की कोई भी सीढ़ी पार करने के लिए ये तैयार रहते हैं। और ऊपर से इनके पास धर्माधिता में अंधी हुई एक पूरी सांप्रदायिक जमात है जो न तो भला देख पाती है और न

मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मानते हैं कि मोदी-शाह की जोड़ी

## जनादेश के अपहरण के खिलाफ सड़क ही एकमात्र रास्ता

ही बुरा देखने की उसके भीतर सलाहियत है। उसने सोचने-समझने की क्षमता ही खो दिया है। एक विवेकहीन भीड़ जो हर कीमत पर इनके पीछे खड़ी है। इसके साथ ही आरएसएस जैसे एक संगठन की ताकत इसके पास है जो अपने एंजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ खड़ा है। इसलिए अगले तीन दिन बेहद अहम हैं।

दूर की ही सही इस बात की एक संभावना है कि नतीजे विपक्ष के पक्ष में आएं और मोदी-शाह सामान्य तरीके से सत्ता सौंप दें। लेकिन यह अपवाद स्वरूप ही होगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि चुनाव आयोग और प्रशासन के बल पर एन-केन प्रकारेण ये बहुमत और संभव हुआ तो प्रचंड बहुमत के आंकड़े हासिल कर लें और फिर से सत्ता में बैठ जाएं। लेकिन यह जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। क्योंकि यह चुनाव जनता बनाम मोदी रहा है। और विपक्ष की भी अगुआई जनता ने ही की है।

जमीन पर उतरे हर शख्स को इस बात का आभास होगा कि जनता किस कदर इस सरकार से त्रस्त है। इस बात को शुरू में कोई नहीं समझ रहा था। याद करिए राम मंदिर के उद्घाटन के दौर को। यह सिर्फ मोदी और शाह को नहीं लग रहा था कि उद्घाटन के बाद पूरे देश में राम लहर आ जाएगी और मोदी उस पर सवार होकर सत्ता की वैतरणी पार कर लेंगे।

इस बात की आशंका विपक्ष और सत्ता के खिलाफ काम करने वाले लोगों के भीतर भी थी। लेकिन उद्घाटन के बाद यह अपने तक चलने की भी उम्मीद नहीं है। यहाँ से विपक्ष और सिविल सोसाइटी की भूमिका शुरू हो जाती है। जनता के मैट्टेट को अपहृत करने से बचाने के लिए उसे हर संभव प्रयास करना होगा।

इसमें सबसे पहले इन तीन दिनों के भीतर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि कैसे स्वतंत्र और

निष्पक्ष तरीके से मतों की गणना की गारंटी की जाए। और इस कड़ी में पार्टीयों को अपने कैडरों को मतगणना केंद्रों पर इकट्ठा करना होगा। जिससे किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को रोकने के लिए नौकरशाहों पर दबाव बनाया जा सके। और यह दबाव इस तरह का हो कि कोई उस दिशा में सोचने की हिम्मत ही न करे। बाबजूद इसके फिर भी नतीजा बीजेपी के पक्ष में आता है तो यह चुनाव आयोग और ईवीएम के जरिये ही संभव होगा। जिसकी कम से कम अभी तक विपक्ष के पास कोई काट नहीं है।

ऐसे समय में आयोग और कोर्ट को भले ही औपचारिक तरीके से शामिल किया जाए और उनसे जरूरी गुहार लगायी जाए लेकिन आखिरी रास्ता सड़क का ही होगा। तत्काल विपक्ष और सिविल सोसाइटी को जनादेश के इस अपहरण के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान करना होगा जिससे जनादेश को फिर से वापस हासिल किया जा सके। यह अपने किसी की दूसरी आजादी की लड़ाई होगी। जिसमें दूश्मन कोई अंग्रेज नहीं बल्कि अपने ही बीच के लोग हैं। और लोकतंत्र तथा आजादी को हड्डपने वाले ऐसे लोगों को निर्णायक शिक्षण देनी होगी। अच्छी बात यह है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। और यह एकजुटता सड़क पर भी दिखानी होगी। जरूरत पड़ने पर यह लड़ाई लंबी भी चल सकती है। लिहाजा उसके लिए भी लोगों को मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा।

## भारत के 27 टन विस्फोटक ले जा रहे जहाज को स्पेन ने रोका

### पेज 1 का शेष

सच समने आ जाने के कारण ईरान से संबंध बिगड़ जाते। इसलिए मोदी सरकार ने सच छुना कर अटल बिहारी वाजपेई के समय के 1998 के पाकिस्तान कारगिल युद्ध का एहसान सामने रखा जबकि ना तो वह युद्ध के लंबा चला न ही वहाँ पर किसी के गोला बारूद की आयत की कोई खबर सामने आई और ना ही कोई आयात किया गया। पर ईरान से संबंध ना बिगड़े और फर्जी गाजा में हो रहे सैनिकों की मृत्यु पर बहाये जा रहे घंडियाली अंसुओं की सच्चाई सामने ना आ जाए। इसलिए मोदी ने 1998 के कारगिल युद्ध का इजरायल की गोला बारूद आयत करने का हवाला दिया। जो आम भारतीय नागरिक से लेकर दुनिया के किसी भी देश को गले नहीं उत्तरा।

स्पेन ने इजरायल को भेजे जा रहे 27 टन विस्फोटक से भरे जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया है। स्पेन ने कहा है कि मध्य पूर्व शांति की जरूरत है न कि हथियारों की। इजरायल को इस समय गाजा युद्ध को देखते हुए हथियारों की सख्त जरूरत है।

भारत ने गाजा युद्ध में फंसे इजरायल को हथियार भेजे हैं। भारत ने यह कदम तब उठाया है जब इजरायल को अमेरिका ने हजारों बम की सप्लाई को रोक दिया है। पिछले 8 महीने से हमास के साथ जंग में इजरायल के हथियारों का जखीरा खाली हो गया है और उसने दोस्तप भारत से मदद मांगी थी। भारत ने इजरायल को हथियार भेजा था। भारत ने यह कदम तब उठाया है जब इजरायल को अमेरिका ने हजारों बम की सप्लाई को रोक दिया है। दरअसल यह जहाज भारत से इजरायल की यात्रा कर रहा है और इतनी लंबी यात्रा के दौरान उसे जरूरी सामान फिर से भरना है। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा, 'हमने इस शिप की पहचान कर ली है और हमने उसे अपने यहाँ रुकने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। मैं आपको कह सकता हूं कि यह



ने डेनमार्क के झंडे वाले इस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर भारत से भेजा गया 27 टन विस्फोटक लदा हुआ था। उसने कहा कि मध्य पूर्व को शांति की जरूरत है, न कि और ज्या दा हथियारों की। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनेल अल्ब्रेस ने कहा, 'ऐसा पहली बार है जब हमने यह किया है कि ये खेप लेकर इजरायल जा रहा है और वह स्पेन के बंदरगाह पर रुकने की इजाजत चाह रहा है।'

इस जहाज का नाम मरित्रीय डेनिका है और उसने कार्टेंगो में 21 मई को रुकने की इजाजत मांगी थी। दरअसल यह जहाज भारत से इजरायल की यात्रा कर रहा है और इतनी लंबी यात्रा के दौरान उसे जरूरी सामान फिर से भरना है। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा, 'हमने इस शिप की पहचान कर ली है और हमने उसे अपने यहाँ रुकने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। मैं आपको कह सकता हूं कि यह

किसी भी ऐसे जहाज के लिए प्रति हमारी सतत नीति है जो इजरायल के लिए हथियार या उससे जुड

## राष्ट्रीय राजमार्ग डकैती प्राधिकरण, बड़े राष्ट्रीय स्तर के डकैतों का अड्डा

## सड़के कैसी भी हों, गुंडागर्दी कई गुना लूट पूरी

सूचना के अधिकार में  
जानकारी की अपेक्षा  
जालसाज जानकारी  
छुपाने के घड़यंत्र के  
लिए साधनों का  
अभाव और अपील के  
लिए कहता है  
5 से 15 किमी  
सड़कों पर वसूली के  
बाद भी 80 किमी से  
ज्यादा तेज गाड़ी  
चलाना संभव नहीं

भारत में भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत वाहन चालकों से मोटी वसूली के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई पिछले 10 सालों से जिसका मंत्री नितिन गडकरी अपने आप को बहुत पाक साफ बताते हैं पर अधिकांश पिछले 10 सालों के किए गए ठेके अपने ही मंत्रालय से जारी है। एसओआर से कई गुना ज्यादा के खर्च दिखाकर भारी भरकम 3 से 5 गुना ज्यादा लागत के तैयार कर मोटे ठेके दिए गए। स्वाभाविक था छोटे ठेकेदार उसमें हाथ नहीं डाल सकते थे और बड़े ठेकेदार सभी मोटे कमीशन पर मोटे पूँजी पतियों को दिए गए। इसके बारे में लगातार छापने पर प्रधानमंत्री मोदी ने चार माह पूर्व भी भोपाल के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय में छापा भी डलवाया था। वर्तमान में पूरे देश में और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत 144955 किलोमीटर सड़के हैं जिसमें मध्य प्रदेश में 9104 किलोमीटर सड़के हैं। इसके संबंध में जब क्षेत्रीय परियोजना प्रशासक सुरेश बांजिल को सूचना के अधिकार में पत्र दिया गया तो हर बार उस हरामखोर ने जानकारी देने की अपेक्षा और जानकारी न देने के बहाने किसान



पत्र का जवाब भेजा और लिख दिया की ज्यादा कुछ है तो आप क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय इ-2, 67, अरेग कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल संपर्क करें।

वैसे भी यह हरामखोर फोन का जवाब सरकारी अधिकारियों का भी नहीं देता। किसी का फोन भी नहीं उठाता और कार्यालय में मिलने जाओ तो व्यस्त होने का नाटक कर मिलने से मना कर देता है। दूसरी तरफ इंदौर से धार मार्ग 50 किलोमीटर पर जो टोल लेबड़ पर लगाया गया है, उसको ठीक 500 मी. पूर्व एक सड़क गांव से होती हुई पीथमपुर की तरफ जाती है। उसे पर इन हरामखोर टोल नाके वालों ने मिट्टी का ढेर लगा दिया है ताकि कोई भी गाड़ी वहां से इंदौर की तरफ नहीं जा सके और जो इंदौर से आने वाली गाड़ियां हैं वह पीथमपुर की तरफ उस गांव के रास्ते से ना निकल सके। जहां तक सड़क का सवाल है तो वहां 50 किलोमीटर के 350 रुपए 16 जाता है और जहां तक इस घर बदतमीज परियोजना अधिकारी सुरेश बंजाल का सवाल है तो लगे हुए 10 साल से ज्यादा होने जा रहा है, परंतु दोनों तरफ के साथ बीच में अभी तक इन्होंने वृक्षारोपण नहीं किया और उसका सारा पैसा हजार कर लिया गया। यह हाल अधिकांश मध्य प्रदेश की और राष्ट्रीय राजमार्गों का है जहां पर 7

से 15 रुपए प्रति किलोमीटर तक प्रति कार वसूली करने के बाद में भी ना तो सड़कों पर धाव किया जाता है ना पत्तियां भरी जाती हैं। यहां तक 10 साल के बाद में भी सड़कों पर 80 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर गाड़ियां उछलती कूदती चलती हैं। जबकि इंदौर उज्जैन 50 किलोमीटर पर मात्र रु. 50 लगते हैं बेशक इस मार्ग पर भी 15 साल गुजर जाने के बाद में अभी तक दोनों तरफ के साथ-साथ मार्ग के मध्य में वृक्षारोपण नहीं किया जिसके लिए मध्य प्रदेश सड़क डकैती विकास निगम का 6 साल से ज्यादा समय से बैठा धोर प्रष्ट सिंहस्थ डकैती का नायक राकेश जैन जिम्मेदार है। यही हाल देवास से शाजापुर-ब्यावरा मार्ग का भी है। यहां पर भी ना मार्ग के दोनों तरफ ना ही बीच में सघन वृक्षारोपण नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की साइट पर भी जो पहले सड़कों के नाम के साथ में लंबाई लागत टोल की जानकारी होती थी। वह भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूट डकैती ब्रष्टाचार छुपाने हटा दी गई है। इस अहमदाबाद-इंदौर मार्ग को बनते हुए 15 साल हो गया परंतु अभी तक पूरा नहीं किया गया पर टोल की डकैती अवश्य पूरी ढाली जा रही है। अभी भी उसका मछलिया घाट वाला हिस्सा पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही जब इसको बनाना शुरू किया गया था तब इसका एस्टीमेट लगभग 450 करोड़ का

घुमाकर जोड़कर लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई बढ़ा उसमें जोड़ा गया ताकि भोपाल से देवास होकर उज्जैन जाने वालों से भी वसूली की जा सके और उज्जैन से देवास आने वालों से भी वसूली की जा सके अभी उसका काम चल ही रहा है यहां तक कि इंदौर-उज्जैन मार्ग पर तपोभूमि के पास उसका अभी ओवर ब्रिज का काम चल रहा है इसके बाद में भी फर्जी तरीके से बीच में टोल वसूली का खेल शुरू कर दिया गया। जबकि तपोभूमि से देवास के 5 किलोमीटर

पहले इंदौर मार्ग पर जोड़ा गया तो वह सड़क सीधी बिना पुराने देवास मार्ग को छुये 10 किलोमीटर कम कर बनाई जा सकती थी। पर इन डकैतों ने उस रोड पर वसूली करने के लिए जानबूझकर उस सड़क को सीधे देवास की पुरानी सड़क से जोड़ उस 27 किलोमीटर मार्ग पर भी डकैती का नया अड्डा शुरू कर दिया। आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शोक पर कोई भी गैर सरकारी संगठन ने या वकीलों के समूह ने अभी तक कोई जनहित याचिका क्यों नहीं लगाई।



प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति
प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति
प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति

## तेज गर्मी में सावधानी आवश्यक, लू लगना कारण व बचने के तरीके

वृक्षों की कटाई पर्यावरण से खिलवाड़, बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिम्मेदार

लू

गर्मी से मृत्यु क्यों होती है?

दिल्ली से आंध्रप्रदेश तक... सैकड़ों

लोग लू लगने से मर रहे हैं।

हम सभी धूप में घूमते हैं फिर कुछ

लोगों की ही धूप में जाने के

कारण अचानक मृत्यु क्यों होती है?

हमारे शरीर का तापमान हमेशा

37 डिग्री सेल्सियस होता है,

इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं।

पसीने के रूप में पानी बाहर

निकालकर शारीर 37 डि

सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता



और रक्त में उपस्थित प्रोटीन पकने लगता है (जैसे उबलते पानी में अंडा पकता है) स्नायु कड़क होने लगते हैं इस दौरान सांस लेने के लिए जरूरी स्नायु भी काम करना बंद कर देते हैं। शरीर का तापमान जब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तब रक्त गरम होने लगता है

ब्लडप्रेशर कम हो जाता है, महत्वपूर्ण अंग (विशेषतः ब्रेन) तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है।

व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके कारण एक-एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते हैं, और उसकी मृत्यु हो जाती है।

गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ टालने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, और हमारे शरीर का तापमान 37 मेट्रेन किस तरह रह पायेगा इस और ध्यान देना चाहिए। इक्विनॉक्स प्रभाव अगले 5 -7 दिनों में एशिया के अधिकतर भूभाग को प्रभावित करेगा।

कृपया 12 से 3 के बीच ज्यादा घुमाकर जोड़कर लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई बढ़ा उसमें जोड़ा गया ताकि भोपाल से देवास होकर उज्जैन जाने वालों से भी वसूली की जा सके और उज्जैन से देवास आने वालों से भी वसूली की जा सके अभी उसका काम चल ही रहा है यहां तक कि इंदौर-उज्जैन मार्ग पर तपोभूमि के पास उसका अभी ओवर ब्रिज का काम चल रहा है इसके बाद में भी फर्जी तरीके से बीच में टोल वसूली का खेल शुरू कर दिया गया। जबकि तपोभूमि से देवास के 5 किलोमीटर

के अंदर रहने का प्रयास करें।

तापमान 40 डिग्री के आस पास विचलन की अवस्था में रहें।

यह परिवर्तन शरीर में निर्जलीकरण और सूर्योत्तिप की स्थिति उत्पन्न कर देगा।

(ये प्रभाव भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूर्य चमकने के कारण पैदा होता है।)

कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें।

किसी भी अवस्था में कम से कम 3 ली. पानी जरूर पियें।

किंडनी की बीमारी वाले प्रति दिन कम से कम 6 से 8 ली. पानी जरूर लें।

जहां तक सम्भव हो ब



**सेहत के लिए जरूरी है सही वक्त पर सही चीजें खाना**



मिलावटों के बारे में अक्षरता कहा जाता है कि यह पौराण की विभिन्न गुणितों के बीच एक अक्षरता लगाने वालनवान पर पूरा ध्वनि-नवीं देती है। इसको कल से पहले ही कि उन्हें इस वाक का यहाँ ही वही होता था कि विभिन्न विषय सम्बन्ध का व्यापक वर्णन करती है। यदि आपसी यह सबकाल सूखा जाए, तो विषय वाकाप लहरी व्यापक यह यहाँ ही रुक जाया जाता है औ यह अप्रकाश व्यापक कुछ भी ही नहीं है। इसीसे युक्त एक महाभास्तुरी याकल यह भी है कि विषय वाकने के बारे में विलास जारी है। नहीं तो अक्षरता इस एकीकरण से अद्यतन बनी रहती है कि महीने आकाश के साथ लहरने वाली यह एक सभ्य पर व्यापक जारी ही रहता था, जिसको सेवन निर्भर होती है। फिर सबका विषय वाक्या जारी भाषण इसके बारे में भूमि- दिन की गुरुवार के लिए ज्ञानकर्ता यही गुरुवा का नमस्कार गमने वालतर्ही होता है। नमस्कार वे वीरेन्द्र, चक्र, दूष, हट, जग, या इनकी घोषणा ले सकती है। वर्षी के प्रति जानकारी बल्लभ लहरी के लिए विषय वाक में विभिन्न नुकसानपूर्ण हो सकता है। पातला यिदि होने वाली, लेखित एवं वहाँ होना वाली है विभिन्न लहरीक इसमें (प्रिंटिंग) की समस्या ही नहीं है। यदि आप एक्सरसमाज के गवाहों के लिए सुन्दर लालची जड़ता है तो योगा का लक्ष्मणसंसाकृत कारण के बाद कुछ न कुछ जान रहा है।

**कहरे-** आप दिन में ज्यादा कुछ नहीं खाती तो जरूरी है कि रात का खाना आप समय पर खाए। शाम के समय ज्यादा भूख लगने के कारण ज्यादा खाने की गुजाइश होती है। इसलिए आप रात का खाना सही समय पर खालिया जाये तो यह आसानी से पच जाता है और एसिडिटी की भी समस्या नहीं होती।



मेरे कानवाल छाती पर  
एक जो मिलती है चलिंग पर  
खाली न रुपने के बावजूद एक्सिकटी

सा रीत की सामग्री भी नहीं होती। नक्काश, लेंच और डिनर में खाले पूरा खाना - कुछ लोग यहाँ जब तक न खाएँ तभी खाना खाना है और बीच-बीच में लोटी बोला कुछ लोगों ने भी जबरदस्त नहीं पढ़ती। परन्तु अब एक यहाँ पूरा खाना नहीं खाती तो बोइंग-बोइंग व्हेसलाइंग में कुछ तो कुछ खा जाती है और बीचिकड़ा का पूरा खाना है।

शाम के समय में हल्की बैंगनी- लंच और शाम के समय में ज्ञान रीप न्यूनता हो जाता है पृथक् भी ज्ञान जाता है। ऐसे में कहीं स्ट्रिंग चॉक, डिम्बल, मटोरोंगा,

नववीन या ज्ञान  
केन्द्रका तरे भूमि पृष्ठ से हैं। इसमें  
की समय अपार कार्यालयहुए भैंग  
की वाहाप भूमि तभी का हाल दीवार  
होते भालिए।

एक दिन बापां, एक दिन बुड़ा  
बहिर आये—आगे आये एक दिन तीनों  
बच्चों में जिसी बाहर सोनी है तो उसले  
दिन बापों के इन बच्चों में भी यह  
बदलता आये बदलता है। एक दिन  
आगे जन्मता आया जिसका जन्म तो  
इसका जन्मता यह कहत नहीं है कि  
आप आपां दिन खुद दिन भूल रहे हों।  
ही, इसमें बदल यह कि आप आपां  
दिन यिन्हें ताजे पातों पर निपते रह  
राहती हैं। इससे आपां बदलता ही  
जिसका अनुभव है।

**महिलाओं के लिए फायदेमंद है प्रतावरी की चाय**

उ के अलांक-अस्त्र पहुँची पा  
हैं वहाँ हामीनाल कदमों  
का, महिलाओं के जहाँ पा  
वक्षी अस्त्र होते हैं। कर्त्ता ये  
हैं वहाँ शास्त्रों का उत्ता-  
यात्रा के रास्ते, महिलाओं  
को बेताएं और गिरिधरों द्वेष  
प्रभावित होती है। इमरिए, अ  
के अलांक-अस्त्र पहुँची पा  
से हठमंड रहने के लिए,  
महिलाओं को छापू और स्ट्रीन  
में बुध खास बदलाव करने  
की है। वहाँ हाथीम भी महिलाओं  
को लेहु के लिए बदलावें होते  
हैं। 43 वाली उड़ाने के बाद सीहामंड  
खाने और एक्षियन के बादन को  
कम करने के लिए, काल खास



चीजें चाहता है। इसमें सही वाक्य हैं 2 लार्ज को चाहे, लॉट में उत्तम अनुभव होता है।

तात्परता थी।  
वहिनीयों के लिये तात्परता अनु-  
पलाभ हमें है और इसमें महिनायों की  
कई विचारोंमें का इतना उत्पन्न  
हो जाता है कि अन्योंना को देखने  
करने का बहुत बहुत है।

इसमें मेनोपौज के सम्बन्ध में कम होते हैं।  
इसे परावृत्त दृश्य में भी छहर में जास्तिल किया जा सकता है।  
यह चिह्नोंमें भी पारिवर्तन

मुख्यतरं मैं जागरूक हूँ।  
इससे उत्तरवेशन वीं जुहो दिक्षार्थी  
से भी यहाँ मिलती है। इस चार ने  
दिक्षा और जीवन विनाश की है।

45 के बाद महिलाएँ जल्दी खोरिया की

#### 四、總結

भारतीय एक सुप्राकृति है। इसे नूं तो हर उम्मीद की मालिनीओं को उड़ान में जरूरीत करना चाहिए। लौकिक रुपानक, ४०-५५ वर्ष की उम्मीद में इसे उड़ान सुना चाहिए। इसका मैला बहुत तरीकों में किया जा सकता है। इसकी वापर भी बेस्ट प्रॉफेशनल होती है। इसमें आवारण, कैलिग्राफी और अन्य कई जगहों प्रियतमा वापर आते हैं। वाह याथ स्टार्टअप्स को सुप्राकृति है। साथ ही, नेटवर्क, संचारणों और यूट लिंकिंग को भी इस करती है। यह सुधारने के महत्वपूर्ण बहुत भी काम करती है।

इस वायर, 45 की उम्र के बाबू होमे जाने जीतों के दौरान को कब्ज़ करने के लिए भी ऐसा फार्मार्डर है। 45 से अधिक उम्र की घटितारा, इन 2 वायर को बाहर से उपलब्ध रखायें रखें।

## तेज तापमान, गर्मी की लहर का असर पड़ेगा खाद्य पदार्थों, पानी और खेती पर भी

पेज 8 का शेष

मौसम इस पानी का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे लोगों के लिए पीने के साथ-साथ मवेशियों के लिए, चारा, खेती आदि। 'बागवानी' के अलावा, जो मानसून से पहले भी प्रभावित हो सकता है, मवेशियों के लिए चारे की चुनौतियाँ होंगी। इस समय फसलों की बुआई कम होती है, इसलिए यहाँ थोड़ी राहत मिल सकती है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में कुछ हद तक बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लेकिन सूखी ज़मीन के कारण किसानों के लिए जून में बुआई की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है, सबनवीस कहते हैं।

हालांकि, आशा की किरण यह है कि वर्ष की शुरुआत से अल नीनों की स्थिति कमज़ोर हो गई है और वर्तमान में, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम स्थिति बनी हुई है। नवीनतम मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि आगामी सीज़न के दौरान अल नीनों स्थिति की ताकत कमज़ोर होने और उसके बाद तटस्थ होने की संभावना है। मानसून सीज़न के दौरान ला नीना की स्थिति विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं।

अल नीनों पूर्व और मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में सतही महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने के चरण को संदर्भित करता है, जिससे हवा के पैटर्न में बदलाव होता है जो दुनिया के कई हिस्सों में मौसम को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर हर तीन से छह साल में होता है।

भारत में तापमान और मानसून महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जो पहले से ही खाद्य-मूल्य आधारित मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। चावल और गेहूं दो मुख्य खाद्य पदार्थ, जो मानसून और गर्मी पर निर्भर हैं, अनिश्चितता की स्थिति में हैं जिसके आईएमडी का पूर्वानुमान उत्साहवर्धक नहीं है। 'सामान्य से अधिक गर्म तापमान तत्काल अवधि में संबिल्यों और फलों के लिए मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे गर्मियों की शुरुआत में कीमतों में सामान्य मौसमी बुद्धि बढ़ सकती है। इसके अलावा, सामान्य से अधिक गर्म तापमान जलाशय के स्तर को प्रभावित कर सकता है।

ए सामान्य और अच्छी तरह से वितरित मानसून फसल उत्पादन में सुधार और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी की कुंजी होगी, जो क्रमशः ग्रामीण और शहरी मांग को बढ़ाने में मदद करेगी, 'आईसीआरए भारत की मुख्य अर्थशास्त्री, प्रमुख अनुसंधान और आउटरीश अदिति नायर कहती हैं चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और उपभोक्ता। गेहूं चावल के बाद भारत में बोया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न है, जिसे अक्टूबर-नवंबर के दौरान बोया जाता है और फरवरी-मार्च में काटा जाता है। भारत का गेहूं स्टॉक सात साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है 31 दिसंबर, 2023 को, जब भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने सरकारी गोदामों में 16.35 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष 17.17 मिलियन मीट्रिक टन था, घेरेलू आपूर्ति में गिरावट के बाद भारत ने मई 2022 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया उत्पादन और एक यहावाकांक्षी निर्यात लक्ष्य। विषयन वर्ष 2022-23 में, भारत ने लगभग 10 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने की योजना बनाई, लेकिन लगभग 5 मिलियन टन की शिपिंग हुई। एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, मेरे 2023-24 अप्रैल-मार्च में भारत की गेहूं की फसल साल-दर-साल थोड़ी कम होने की संभावना है, 107 मिलियन-108 मिलियन टन, क्योंकि बाजार सहभागियों ने फसल के तहत स्थिर एकड़ के बावजूद पैदावार में मामूली गिरावट देखी है। 13 विश्लेषकों और व्यापारियों के कमोडिटी इनसाइट्स सर्वेक्षण में पाया गया। व्यापार अनुमान कृषि मंत्रालय के MY 2022-23 अनुमान 110.55 मिलियन टन से कम है। मेरे 2023-24 के लिए, मंत्रालय ने 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

यदि ला नीना वास्तव में जून के बाद विकसित होता है, तो यह एशिया के लिए सावधान योग्य समाचार होना चाहिए, क्योंकि यह आम तौर पर अधिक वर्षा लाता है और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से अनाज (चावल सहित) जैसी वर्षा पर निर्भर फसलों के लिए, नोमुग के मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा कहते हैं। वर्मा के अनुसार, निकट अवधि में, कम स्टॉक के बीच उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौती बनी रहने की संभावना है; हालांकि, वर्ष के अंत में बेहतर फसल की उमीद से 2024 की दूसरी छामी में अनाज की कीमतों पर लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर अगर इसके परिणामस्वरूप भारत के चावल निर्यात प्रतिबंध भी हटा दिए जाते हैं।

## संचालक संयुक्त उप सहायक संचालकों की विक्रेताओं से वसूली कर लूट की छूट

पेज 8 का शेष

इंदौर उज्जैन संभाग के उपसंचालक जिला कार्यालयों में बैठे अधिकांश उप संलालकों सहायक संचालकों कर्मचारियों को वर्षों से एक ही स्थान व पदों पर जमें हुए हैं। जिनकी वर्षों से रूकी हुई पदोन्नतियों को दिया जाना चाहिए। और तत्काल स्थानांतरण करने के साथ-साथ सभी कृषि कार्यालय में मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों की तरह यहाँ भी कर्मचारियों अधिकारियों की भारी कमी है उनकी भी भर्ती किया जाना चाहिए ताकि एक ही पद पर वर्षों तक धोर धूर्त अधिकारी जमे रहकर किसानों का शोषण न कर सके। दूसरी तरफ सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सारी 25 बिंदुओं की जानकारी को तत्काल अपलोड करवा कर प्रदेश के किसानों को समुचित सूचनाओं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वे जानकारी के अभाव में परेशान ना हों।

## इवीएम के षड्यंत्रों से लोकतंत्र की हत्या

पेज 1 का शेष

ताकि वह गुलाम आपके हिसाब से नाच कर आपकी आज्ञा का पालन करते रहें। उस कार्य प्रणाली पर चलते हुए आरती के साथ पहली पंचवर्षीय में सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी में 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार धंधे बर्बाद कर 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। जैसा की लोकतंत्र की हत्या कर एक देश एक चुनाव, करने का जो षड्यंत्र किया गया है। उसमें विषय को अब मुंह खोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यदि 400 पार का जो षड्यंत्र किया है। उसमें लोकसभा में अब विषय नाम का कोई भी सदस्य होगा ही नहीं, जो होंगे वह किसी न किसी बहाने जेल में डाल दिए जाएंगे पूरे देश में आने वाले 5 सालों में ब्रष्टाचार तबाही और बर्बादी की नई कहानी लिखी जाएगी।

जब तक देश से इवीएम नहीं हटाई जाएगी। तब तक लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। एक तरफा तानाशाही का शासन चलाया जाएगा। देश को नशे की गर्त में डुबोकर पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाएगा शिक्षा का निजीकरण चल ही रहा है जहाँ लूट का तांडव गरीबों मध्यम वर्ग की बच्चों को शिक्षा के संस्थानों तक न पहुंचने की दोस्त के नाम पर अब इतने सारे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है की एक आम गरीब आदमी का बच्चा उन दस्तावेजों को बनाने में ही 10-20 हजार रुपए खर्च करने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसकी मासिक कमाई से कहीं ज्यादा होता है।

आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्थाएं खत्म कर दी जाएगी। अभी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में 40 से बच्चों को कहीं एक वर्ष से कहीं 2 वर्ष से छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली हैं जो भविष्य में पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी।

परिणाम घोषित होने के बाद में यदि जनता ने सड़कों पर निकलकर इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन नहीं किया तो सन 2029 तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ होने के साथ पहली पंचवर्षीय में सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा का गेहूं चावल खाकर जीवन यापन करते हुए दुनिया की गरीबों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर होगा। औद्योगिक विकास की तो दूर चीनी माल से पूरे देश की सारी दुकान भरी पड़ी होंगी। बैंक प्रशासनिक तंत्र तानाशाहों से ज्यादा भाजपा के नेताओं के इशारे पर नाचने वाला कठपुतली होगा। जिसके लिए देश का प्रशासनिक तंत्र ही जिम्मेदार होगा।

वर्तमान में लोकसभा चुनाव जीत के लिए जो गुजरात का तरीका अपनाया गया जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाकर आखरी में गिनती के समय आसानी से अपनी जीत दर्ज करवाने के बाद में भी विपक्षी दलों के साथ जनता की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई और अपलोड करना चाहिए ताकि जनता लोकतंत्र के इस महायज्ञ की सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम देख सके परंतु ऐसा कभी होता नहीं और ना ही किया जाएगा।

उल्टे ही जब मतदान के बाद तत्काल हर मतदान अधिकारी को फार्म 17C की कार्पियां हस्ताक्षर करके सभी संतों को देनी चाहिए नहीं दी गई और जानबूझकर मतदान नहीं हुआ पर जानबूझकर उसको बढ़ाकर 60-70-80% तक ले जाया गया, जैसा कि इंदौर में ही देखने को भी मिला। अब प्रशासन पर प्रशासनिक अधिकारी भारतीय प्रतिशत बढ़ाना के अधिकारियों को नहीं भाजपा के नेताओं का चलता है। इसी षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए जानबूझकर ढेर ही महीना लंबा तक चुनाव खींचे गए हैं ताकि आसानी से मशीनों में मतदान की सभी प्रकार की मतदान बढ़ाने की हरेफर की जा सके। जिसका परिणाम 4 जून को शाम तक आ जाएगा, जबकि सच यह है कि मतदान मशीन खोलने का नाटक किया जाएगा। गिनती तो पिछले 10 सालों में कभी भी दंग से पूरी नहीं की गई। क्योंकि

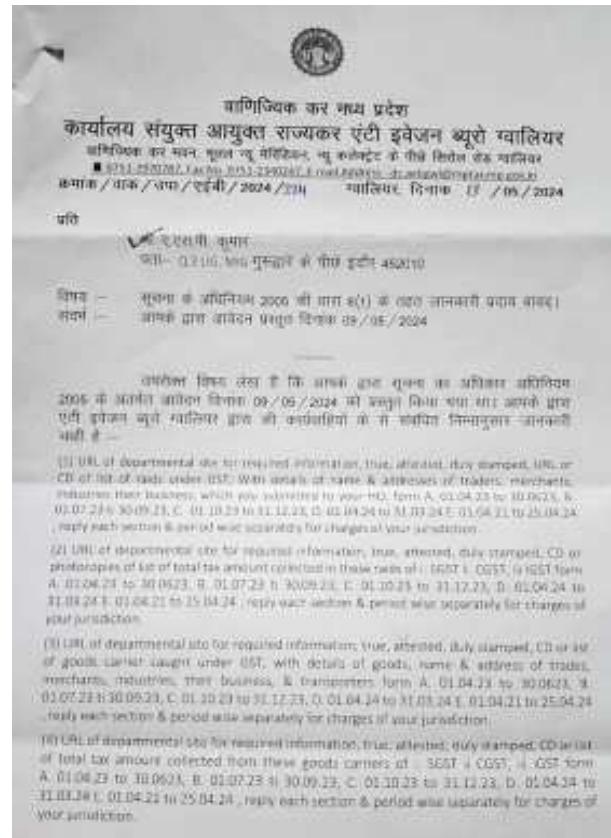
का सच आवश्यकता के अनुकूल जनता के सामने लाते रहने पर यह अधिकारी नेता पुलिस आइएस आपसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे आ

वाणिज्य कर मुख्यालय से वृत्तों तक भ्रष्ट जालसाजों का अड्डा

## सब बाप की जागीर, सूचना अधिकार में कैसी व क्यों जानकारी

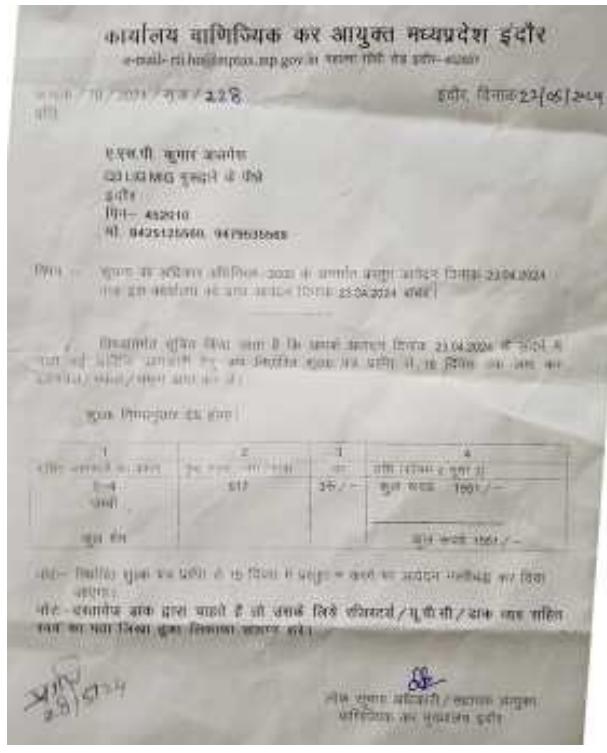
सूचना के अधिकार में  
जानकारी न देने के  
लिए सारे हरामखोरों  
के अपने तक  
19 वर्ष बाद भी 25  
बिंदुओं की जानकारी  
साइट पर नहीं

मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मुख्यालय इंदौर से लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे 25 से ज्यादा संभागों और 80 से ज्यादा वृत्त कार्यालयों में जीएसटी लगने के 7 साल बाद भी अभी तक सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 25 मिनट की जानकारी को अपलोड नहीं किया गया और जानकारी मांगने पर 6 एंटी इवेजन ब्यूरो से लेकर मुख्यालय में बैठे घोर मक्कार कामचोर अधिकारी समय पर जवाब देने की अपेक्षा पूर्व की तारीख में 30 दिन के समय अवधि के बाद जवाब देते हैं दूसरी तरफ जब जीएसटी में और मध्य प्रदेश सरकार पिछले 14 वर्षों से यह दावा कर रही है कि उसकी सारी जानकारी सारा काम कंप्यूटर पर होता है तो भी 14 साल के बाद में भी सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 जे चार के अंतर्गत ना तो कद में दी जाती है और ना ही अपनी साइट पर अपना ग्राहिताचार छुपाने अपलोड की जाती है। अच्छा इन डिवीजन ब्यूरो को पत्र देने पर वह अपने आप को



सैन्य व अर्धसैनिक बलों की श्रेणी में रखकर सूचना के अधिकार से ऊपर मानते हैं जबकि 6 के 6 एंटी विजन ब्यूरो में बैठे उपायुक्तों से लेकर सारे सहायक आयुक्त वाणिज्य कर अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कर निरीक्षक तक सब मोटा पैसा खर्च कर वहां पदस्थ होते हैं वैसे भी वहां चुन चुन कर मोटा पैसा पूर्व के पदों पर कमाकर खर्च करने वाले ही

पदस्थ हो पाते हैं। फिर कुछ अधिकारी तो जोड़-जोड़ में इन्हें चालाक होते हैं कि वहन केवल मुख्यालय में बैठने के साथ और एंटी इवेजन ब्यूरो में भी वर्षों से कुंडली जमाये बैठे हैं। इस विभाग में अधिकांश अधिकारी जो मुख्यालय में बैठे हैं। घोर भ्रष्ट होने के साथ-साथ जालसाज होने के कारण ही उनको मैदानी पदस्थी की अपेक्षा मुख्यालय



में संलग्न कर दिया गया है। इसमें एक जबलुरु से आए नारायण मिश्रा जो पूर्व में इंदौर में रहकर काफी कर्मकांड कर चुके थे। पुणे मुख्यालय में बैट एवं गेट हैं जिनके पास कर्मचारियों अधिकारियों के आवास आवंटन का कार्य भी है अपने ही विभाग के जिन कर्मचारियों अधिकारियों में 10 साल से आवास के आवंटन के लिए आवेदन दे रखा है उनका आवंटन न कर उनके आसपास के खास अधिकारी कर्मचारियों को ले दे कर तत्काल में ही आवंटन कर दिया जाता है।

जिसकी अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत किया स्पष्ट है कि कोई भी संभागीय अधिकारी ही लोक सूचना अधिकारी हो सकता है और उसकी सहायक अधिकारी सहायक लोग सूचना अधिकारी होगा जिसकी विरुद्ध अपील उसका वरिष्ठ अधिकारी ही सुनेगा के विपरीत तीन हरामखोरों ने संभागीय उपायुक्तों को अपने ही विरुद्ध आवेदन का अपीलीय अधिकारी भी बना रखा

है। स्वाभाविक है भाई अपने हर कृत्य को कानूनी बताकर अपील को नस्ती बद्ध कर देता है। यही हाल मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी का भी होता है आखिर फिर सूचनाओं जानकारियां क्यों देंसब उनके बाप की जागीर है कानून उनकी खेल और जनधन से मिलने वाला वेतन सुविधायें उनकी जागीरदारी का हिस्सा।

मुख्यालय में बैठकर पूरे प्रदेश के कार्यालयों के लिए सबसे मोटा आइटम कंप्यूटर प्रिंटर व अन्य सामग्री खरीदने में हर दो-तीन वर्ष में मोटे कमीशन पर किया जाता है। सरकारी गाड़ियों की लगभग इसलिए, नहीं जा सकती क्योंकि भाई बहन के बाप की जागीर हैं जो जहां चाहेंगे जैसा चाहेंगे अपने व्यक्तिगत आने जाने घुमने फिरने परिवार को घुमाने में बिना लाख बुक में एंटी किये आयुक्त से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी करते हैं इसलिए लगभग की कॉपी उनकी व्यक्तिगत बिपति है उसकी छायाप्रति नहीं दी जा सकती। यह बहुत छोटे-छोटे मामले हैं, सारे बड़े मामले रिफंड छापेमारी वाहन पकड़ने आदि में किये जाते हैं। जो प्रदेश की वाणिज्यिक यह माल व सेवा कर की वसूली में प्रदेश को भारी राजस्थानी पहुंचते हैं अब जो कि मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी जालसाजियों में उलझे हैं। तो जानकारियां कैसे दें।

## यूक्रेन को अमेरिका नाटो हथियार दे भड़का रहे युद्ध

पेज 1 का शेष

24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से रूसी नेता ने बार-बार परमाणु हथियारों का उपयोग करने की अपनी तत्परता के बारे में बात की है। सबसे हालिया ऐसी धमकी पिछले महीने उनके राष्ट्र के संबोधन में आई थी, जब उन्होंने पश्चिम को चेतावनी दी कि यूक्रेन में लड़ाई में अपनी भागीदारी को गहरा करने से परमाणु युद्ध का खतरा होगा।

बुधवार तड़के जारी रूसी सरकारी टेलीविजन के साथ एक साक्षात्कार में जब पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी यूक्रेन में युद्धक्षेत्र में परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार किया है, तो पुतिन ने जवाब दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को एक अनुप्रवी राजनेता के रूप में वर्णित किया जो तनाव के संभावित खतरों को पूरी तरह से समझते हैं। जब पुतिन की टिप्पणियों पर संयुक्त राष्ट्र महासंघ एंटेनियो गुरेस की प्रतिक्रिया मांगी

गई, तो प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि 'सभी बयानबाजी से गलत अनुमान लगाया जा सकता है या दुनिया के लिए स्पष्ट विनाशकारी परिणामों के साथ तनाव बढ़ सकता है।'

एक विस्तारित नाटो अपनी विविधता को ताकत के रूप में उपयोग करता है। सदस्य सैनिक जानते हैं कि रूस देख रहा है।

पुतिन की टिप्पणियां पश्चिम के लिए एक संदेश प्रतीत होती हैं कि वह यूक्रेन में अपने लाभ की रक्षा के लिए सभी तरीकों का उपयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश के सुरक्षा सिद्धांत के अनुरूप, मॉस्को 'रूसी राज्य' के अस्तित्व, हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता' के लिए खतरे की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार है।

लिथुआनिया के विदेश मंत्री गैब्रियलियस लैंड्सबर्गिस ने हाल ही में इस बात पर अफसोस जताया कि पश्चिम भी अक्सर रूस के संबंध में स्वयं द्वारा थोपी गई 'लाल रेखाओं' से खुद को बांध लेता है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की उस टिप्पणी का भी स्वागत किया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों को भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पुतिन ने बिडेन और उनके प्रश्नाओं के बारे में जवाब दिया कि अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजने जा रहा है। उन्होंने आगे राष्ट्रपति चुनाव को पटरी से उतारने के लिए अपने लोगों को भेजा है। उन्होंने कहा, 'यह दुश्मन के खिलाफ हटने का ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि रूसी संघ के लिए सुरक्षा की गारंटी से जुड़ी एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए।'

पुतिन ने कहा कि रूस के

अंदर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में हाल ही में बढ़ाती देश के तीन दिवसीय राष्ट्रपति चुनाव को पटरी से उतारने के प्रयासों का हिस्सा है, जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है और असहमति और सञ्च नियंत्रण पर उनकी लगभग पूरी कार्रवाई को देखते हुए, वह भारी बहुमत से जीतने के लिए तैयार हैं। रूस की राजनीतिक व्यवस्था पर

रूसी अधिकारियों ने बुधवार तड़के यूक्रेन द्वारा एक और बड़े हमले की सूचना दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई सुरक्षा त्रुट्यालयों को जारी किया गया है। क्रेपलिन और विलेवोवा को हवाई विमानों को हारा दिया गया है। यह दुश्मन के लिए एक अपार्टमेंट इमारत के मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। ब्रेकीय प्रशासन के अनुसार, उत्तरी शहर सुमी में एक पांच मंजिला इमारत पर गत भर रूस से लौंच किए गए हैं।

ड्रोनों में से एक ने रियाज़ान क्षेत्र में

एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे कम से कम दो लोग घायल हो गए और आग लग गई। एक अन्य को उस समय मार गिराया गया जब वह सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक रिफाइनरी के पास पहुंच रहा था। रूसी क्षेत्र के अंदर सुविधाओं पर ड्रोन हमलों के साथ-साथ, यूक्रेनी बलों ने समुद्री ड्रोन और मिसाइलों के साथ काला सागर क्षेत्र में रूस की नौसैनिक कार्रवाई को देखते हुए रखा है। इस सातांत में, रूसी मीडिया ने बताया कि रूसी नौसैना प्रमुख, एडमिरल निकोलाई थेवेनोव को हटा दिया गया था और उनकी जगह उत्तरी शहर सुमी में एक ब्रेकीय प्रशासन के अनुसार, उत्तरी शहर सुमी में एक पांच मंजिला इमारत पर गत भर रूस से लौंच किए गए हैं। इस सातांत में, रूसी नौसैनिक क्षमता को पांच ग्राम ड्रोन ने कहा कि यह दुश्मन के लिए एक अपार्टमेंट इमारत के मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। ब्रेकीय प्रशासन के अनुसार, उत्तरी शहर सुमी म

## 2024 की गर्मी

# तेज तापमान, गर्मी की लहर का असर पड़ेगा खाद्य पदार्थों, पानी और खेती पर भी

भारत में गर्मी और मानसून अभी भी गंभीर बने हुए हैं, और पहले से ही खाद्य-मूल्य आधारित मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। चावल और गेहूं, दो मुख्य खाद्य पदार्थ, अनिश्चितता का समान कर रहे हैं क्योंकि आईएमडी का पूर्वानुमान उत्साहजनक नहीं है।

गर्मी की लहरों के दिनों की अधिक संख्या का चक्र अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि आय, खाद्य मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति और सामान्य से अधिक लूप वाले दिनों की चेतावनी दी है। आईएमडी का कहना है कि अप्रैल 2024 के दौरान, दक्षिणी प्रायद्वीप के कई हिस्सों, उत्तर-पश्चिम मध्य भारत से सटे, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन होने की संभावना है।

अप्रैल-जून के दौरान मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों को अत्यधिक गर्मी का सबसे बुरा प्रभाव झेलने की आशंका है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, इसके

बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक गर्मी की लहर वाले क्षेत्र होंगे।

उत्तर हाँ प्रतीत होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस सत्र में भीषण गर्मी और सामान्य से अधिक लूप वाले दिनों की चेतावनी दी है। आईएमडी का कहना है कि अप्रैल 2024 के दौरान, दक्षिणी प्रायद्वीप के कई हिस्सों, उत्तर-पश्चिम मध्य भारत से सटे, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन होने की संभावना है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, "विंताएँ स्पष्ट हैं।" उनका कहना है कि गर्मी को लेकर चेतावनी अपेक्षित है क्योंकि जलाशयों का स्तर काफी नीचे चला गया है।

यह स्तर क्षमता का 36 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम है, जब यह 43 प्रतिशत था।

"यह मुख्य रूप से वाष्णविकारण के उच्च स्तर के कारण है। यह और भी महत्वपूर्ण है कि मानसून समय पर आए अन्यथा पीने, फसलों (विशेषकर बागवानी), मवेशियों और निर्माण के लिए पानी की कमी हो सकती है," सबनवीस बताते हैं।

ऐसे 150 जलाशय हैं जिनकी निगरानी साप्ताहिक आधार पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है। पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) पर कुल जीवित क्षमता लगभग 179 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है।

भारत में आम चुनावों पर भी तेज गर्मी पड़ने की संभावना है, क्योंकि जलाशयों का स्तर काफी नीचे चला गया है।



मतदान 1 जून को समाप्त होगा।

"लोगों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना होगा और अत्यधिक गर्मी का सामना करना होगा।" उसी समय। हमें चुनावी प्रक्रिया में बेहद सावधान रहना होगा," केंद्रीय पृथक्षी विज्ञान मंत्री विरेन पिंजिजु को कथित तौर पर उद्धृत किया गया था।

जब देश में जलाशयों में जल स्तर बढ़ाने की बात आती है तो

बारिश महत्वपूर्ण होती है। चूंकि मानसून आम तौर पर जून-सितंबर की अवधि में प्राप्त होता है, सीमित राज्यों में उत्तर पूर्वी मानसून का असर होता है, जिसका कार्यकाल अक्टूबर और दिसंबर के बीच छोटा होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जलाशयों में जमा होने वाला पानी अगले तक स्वस्थ स्तर पर रहे। ( शेष पेज 6 पर )

## बोनी के समय किसानों को लूट रहे बीज विक्रेता

# संचालक संयुक्त उप सहायक संचालकों की विक्रेताओं से वसूली कर लूट की छूट



**भारत की ही नहीं वरन्  
विश्व की कृषि में  
अधिकांश कृषक कर्ज में  
जन्म जिएगा और मरेगा**

भारत में गर्मी की समाप्ति पर बरसात का आगमन होता है और बरसात के आगमन पर देश की कृषक पंजाब से केरल और मुंबई से मेघालय मणिपुर तक सब खरीफ की फसलें बोते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि को पिछले 21-22 सालों में पूरी तरह से अमेरिकी बीटी जीएम और हाइब्रिड बीज उत्पादक कंपनियों के हवाले कर दिया गया है चाहे वह बीटी कपास हो या हाइब्रिड सोयाबीन। सबकी बिक्री करने वाले सारे गांवों से लेकर शहरों तक बीज बड़े डीलर डिस्ट्रीब्यूटर विक्रेताओं जिनमें अधिकांश के प्रदेश में कार्यालय

इंदौर में हैं। पूरे प्रदेश की कृषि के लिए बीजों की नियन्त्रण करने वाले उत्तरी अन्य सहायक सामग्री इंदौर में बैठे आप उसकी करता हूं द्वारा ही प्रदेश में आपूर्ति की जाती है।

यही कारण है कि यहां पर बरसों से इंदौर-उज्जैन संभाग के 1.5 जिलों का संयुक्त संचालक बन कर बैठा घोर भ्रष्ट आलोक मीणा मोटी कमाई कर संचालक कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना तक को पहुंचना है और अभी अपने हाल ही में देखा खरगोन-खंडवा-धार आदि में जहां बीटी कपास बोया जाता है। जून का महीना शुरू हो चुका है और बुवाई सिर पर है, बीटी कपास के रु. 800 के पैकेट को 12 से 1500 में विक्रेताओं द्वारा बैठा जा रहा है। जिसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं की असली है या नकली। और

बुवाई के बाद उसे इच्छित परियाम प्राप्त होंगे। जिसके लिए लंबी लाइन सुबह 3:00 बजे से लगानी शुरू हो जाती थी। सूत्रों के अनुसार अधिकांश मामलों में उपसंचालक खरगोन एम एल चौहान, खंडवा में केसी वाक्केल ज्ञाबुआ नवीन सिंह रावत ने मोटी कमाई की थी और विक्रेताओं को कृषकों को लूटने की खुली छूट दे दी थी। इंदौर संभाग के इंदौर, धार, ज्ञाबुआ खंडवा खरगोन बुरहानपुर अलीराजपुर बड़वानी उज्जैन संभाग के उज्जैन देवास शाजापुर मंदसौर नीमच रत्लाम आगर मालवा में यही हाल सोयाबीन के बीजों के लिए भी हुआ। जो सोयाबीन मंडी में साठे चार हजार पांच हजार रुपए कुंटल बिका वही सोयाबीन बीज के लिए प्रमाणीकृत 10 से रु. 12000 किंवदं बिक रहा है। पिछले कई सालों से इंदौर-उज्जैन संभाग का एक ही प्रभारी संयुक्त संचालक के रूप में आलोक मीणा पदस्थ हैं जो अपना निजी बीज आपूर्ति का व्यवसाय करते रहते हैं कई सप्ताहों तक न इंदौर कार्यालय में आते हैं ना उज्जैन के कार्यालय में आते हैं यही कारण है की महीनों से सूचना अधिकार के आवेदन अपीलों और शिकायतों का निराकरण का नहीं कर पाते हैं।

( शेष पेज 6 पर )

साप्ताहिक

# समय माया

samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़वानों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन ( प्रिंट एवं वीडियो ) के लिए संपर्क करें

मग्ना के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com  
samaymaya@rediff.com